आकाशवाणी केन्द्र शिमला
03.02.2025 / प्रादेशिक समाचार / 1800बजे

सीएम बैठक

प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024–2025 के दौरान नाबार्ड से 903 करोड़ 21 लाख रुपये की एक सौ 27 परियोजनाएं स्वीकृत करवाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला में वार्षिक बजट 2025–2026 के लिए कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति ज़िलो के विधायकों की प्राथमिकता को निर्धारित करने के उद्देश्य से आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में से 4 सौ 12 करोड़ 75 लाख रुपये की विधायक प्राथमिकता योजनाएं लोक निर्माण विभाग और एक सौ 79 करोड़ से अधिक की 23 विधायक प्राथमिकता योजनाएं जल शक्ति विभाग की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष मार्च माह तक नाबार्ड से और अधिक विधायक प्राथमिकताओं को स्वीकृत करवाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले दो वर्षों में प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, आधारभूत ढांचा, कृषि, बागवानी, उद्योग और महिला सशक्तिकरण व बाल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। बैठक में विधायकों ने अपने–अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर मांगे रखीं। इस अवसर पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

जयराम ठाकुर

इस बीच भाजपा विधायक दल ने विधायक प्राथमिकता बैठकों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आगामी वित्त वर्ष को लेकर विधायक अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं को बताते हैं कि ताकि उनके लिए बजट का प्रावधान हो सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बीते दो वर्षों में विपक्ष के विधायकों ने जो प्राथमिकताएं दी थी उनकी अभी तक डीपीआर ही नहीं बनाई गई है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भी केवल मुख्यमंत्री के करीबी विधायकों की योजनाओं को ही स्वीकृति मिल रही है, इसलिए विपक्ष के विधायकों ने विधायक प्राथमिकता की बैठकों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।

विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार केंद्र सरकार के पैसे का दुरूपयोग कर रही है और मनरेगा व रेलवे जैसी परियोजनाओं का हिस्सा भी राज्य सरकार नहीं दे रही है।

सिकंदर कुमार

राज्य सभा सांसद सिकंदर कुमार ने हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों व अन्य तीर्थस्थलों पर एस्केलेटर और लिफ्ट लगाने का केंद्र से आग्रह किया है। वे आज राज्यसभा में शून्य काल के दौरान बोल रहे थे। सिकंदर कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और यहां अधिक मंदिर ऊंचाई पर स्थित है। उन्होंने कहा कि इन मंदिरों तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को सैंकड़ों सीढ़ीयां चढ़नी पड़ती है, जिसमें बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को कठिनाई होती है। उन्होंने कहा कि राज्य के तीर्थस्थलों पर मूलभूत सुविधाएं मिलने से श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा।

सुरेश कश्यप

लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार के बजट में प्रस्तुत प्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रस्तावों को व्यक्तिगत आयकर सुधार की दिशा में अहम कदम बताया है। आज लोकसभा में आयकर प्रावधानों को सरल बनाने के विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग के करदाताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। सुरेश कश्यप ने कहा है कि वर्ष 2020–21 में नई कर व्यवस्था लागू होने के बाद से विभिन्न आय स्लैब में व्यक्तिगत आयकर दरों में लगातार कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय और किराए की आय जैसी कुछ आय के संबंध में स्रोत पर कर कटौती की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

————————————